ISSN (ELECTRONIC): 2945-3135

दलीप सिंह बिष्ट (2026). भारतीय ज्ञान प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में शैक्षिक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम रूपांतरण एवं क्षमता निर्माण: समकालीन राजनीतिक चुनौतियाँ. International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews, 5(8),97-108.

INTERNATIONAL JOURNAL OF
MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & REVIEWS

journal homepage: www.ijmrr.online/index.php/home

# भारतीय ज्ञान प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में शैक्षिक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम रूपांतरण एवं क्षमता निर्माण: समकालीन राजनीतिक चुनौतियाँ

**डा. दलीप सिंह बिष्ट**

असिस्टेंट प्रोफेसर एवं विभाग प्रभारी, राजनीति विज्ञान विभाग, धर्मानंद उनियाल राजकीय महाविद्यालय, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल, भारत.

drdalipbisht@gmail.com

**How to Cite the Article**: दलीप सिंह बिष्ट (2026). भारतीय ज्ञान प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में शैक्षिक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम रूपांतरण एवं क्षमता निर्माण: समकालीन राजनीतिक चुनौतियाँ. International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews, 5(8),97-108.

https://doi.org/10.56815/ijmrr.v5i8.2026.97-108

***Keywords***

ज्ञान-आधारित राष्ट्र निर्माण, भारतीय ज्ञान प्रणाली, राजनीतिक चुनौतियाँ, शैक्षिक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम रूपांतरण, क्षमता निर्माण।

***Abstract***

वर्तमान वैश्वीकरण, तकनीकी नवाचार तथा लोकतांत्रिक जटिलताओं के दौर में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया बहुआयामी हो गई है। अब यह केवल आर्थिक वृद्धि या राजनीतिक स्थिरता तक सीमित नहीं रहकर ज्ञान, मूल्य, कौशल और मानवीय क्षमता के समन्वित विकास पर आधारित होती जा रही है। ऐसे संदर्भ में भारतीय ज्ञान प्रणाली, जिसमें समग्रता, नैतिकता, लोककल्याण, सहअस्तित्व और सतत विकास के सिद्धांत निहित हैं, समकालीन राजनीतिक चुनौतियों के समाधान हेतु एक महत्वपूर्ण वैचारिक आधार प्रस्तुत करती है।

यह शोध पत्र ज्ञान-आधारित राष्ट्र निर्माण की अवधारणा के संदर्भ में भारतीय ज्ञान प्रणाली की भूमिका का समालोचनात्मक विश्लेषण करता है तथा शैक्षिक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम रूपांतरण एवं क्षमता निर्माण के माध्यम से राजनीतिक उत्तरदायित्व, नेतृत्व विकास एवं लोकतांत्रिक सुदृढ़ता को सशक्त बनाने की संभावनाओं का अध्ययन करता है। अध्ययन में यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि शिक्षा व्यवस्था में भारतीय ज्ञान परम्परा के मूल्यपरक एवं व्यवहारिक आयामों को समाहित किया जाए, तो एक उत्तरदायी, सहभागी एवं समावेशी राजनीतिक संस्कृति का निर्माण संभव है।

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

दलीप सिंह बिष्ट (2026). भारतीय ज्ञान प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में शैक्षिक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम रूपांतरण एवं क्षमता निर्माण: समकालीन राजनीतिक चुनौतियाँ. International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews, 5(8),97-108.

## भूमिका:

राष्ट्र निर्माण किसी भी समाज के सतत एवं संतुलित विकास की आधारभूत प्रक्रिया मानी जाती है, जो समय, परिस्थितियों और सामाजिक-राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुसार निरंतर रूपांतरित होती रहती है। आधुनिक युग में राष्ट्र निर्माण की अवधारणा ने एक नए आयाम को ग्रहण किया है, जिसमें ज्ञान, नवाचार, मानवीय संसाधन विकास तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की सुदृढ़ता को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है। वैश्वीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी के तीव्र विस्तार तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बढ़ते प्रभाव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति केवल भौतिक संसाधनों या आर्थिक उत्पादन पर निर्भर नहीं होती, बल्कि इसके लिए ज्ञान-आधारित समाज का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। इस संदर्भ में शिक्षा, प्रशिक्षण तथा नेतृत्व क्षमता का विकास राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाने लगा है, क्योंकि यही तत्व नागरिकों को बदलती राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक चुनौतियों के प्रति सक्षम बनाते हैं।

भारतीय ज्ञान प्रणाली, जो वेदों, उपनिषदों, बौद्ध एवं जैन दर्शन, लोक परम्पराओं तथा विविध सामाजिक-सांस्कृतिक अनुभवों के दीर्घकालिक संचयन से विकसित हुई है, मानव जीवन को समग्रता में समझने की दृष्टि प्रदान करती है। यह प्रणाली ज्ञान को केवल सूचना या तकनीकी दक्षता के रूप में नहीं देखती, बल्कि उसे मूल्य-निर्माण, नैतिक चेतना, सहअस्तित्व, सामाजिक समरसता और लोककल्याण से जोड़कर प्रस्तुत करती है। भारतीय चिंतन परम्परा में शिक्षा को व्यक्ति और समाज के मध्य संतुलन स्थापित करने का माध्यम माना गया है, जिससे नागरिकों में उत्तरदायित्व, संवेदनशीलता और लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का विकास हो सके। इस प्रकार भारतीय ज्ञानप्रणाली राष्ट्र निर्माण को केवल संस्थागत या नीतिगत प्रक्रिया न मानकर एक सांस्कृतिक एवं नैतिक परियोजना के रूप में देखती है, जिसमें प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भूमिका होती है।

समकालीन राजनीतिक परिदृश्य में अनेक जटिल चुनौतियाँ उभरकर सामने आई हैं, जिनमें लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति घटता विश्वास, नेतृत्व संकट, सामाजिक एवं सांस्कृतिक ध्रुवीकरण तथा नीति-निर्माण में असंतुलन जैसी समस्याएँ प्रमुख हैं। ये परिस्थितियाँ यह संकेत देती हैं कि केवल तकनीकी या प्रशासनिक प्रशिक्षण के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इसके लिए ऐसे शैक्षिक पाठ्यक्रमों और क्षमता निर्माण मॉडलों की आवश्यकता है, जो ज्ञान, मूल्य और व्यवहारिक दक्षताओं का समन्वित विकास कर सकें। जब शिक्षा व्यवस्था आलोचनात्मक चिंतन, नैतिक नेतृत्व, संवाद कौशल, सामाजिक संवेदनशीलता और लोकतांत्रिक सहभागिता जैसे गुणों को प्रोत्साहित करती है, तब वह राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बना सकती है। अतः वर्तमान संदर्भ में भारतीय ज्ञान प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा एवं प्रशिक्षण की पुनर्व्याख्या करना न केवल अकादमिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समकालीन राजनीतिक चुनौतियों के समाधान हेतु भी अत्यंत प्रासंगिक प्रतीत होता है।

## शोध के उद्देश्य:

1. ज्ञान-आधारित राष्ट्र निर्माण की अवधारणा का विश्लेषण करना।
2. भारतीय ज्ञान प्रणाली के प्रमुख सिद्धांतों की समकालीन प्रासंगिकता को स्पष्ट करना।
3. शैक्षिक प्रशिक्षण एवं पाठ्यक्रम रूपांतरण की राजनीतिक संदर्भ में भूमिका का अध्ययन करना।

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

दलीप सिंह बिष्ट (2026). भारतीय ज्ञान प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में शैक्षिक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम रूपांतरण एवं क्षमता निर्माण: समकालीन राजनीतिक चुनौतियाँ. International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews, 5(8),97-108.

4. क्षमता निर्माण के माध्यम से नेतृत्व विकास एवं लोकतांत्रिक सुदृढ़ता की संभावनाओं का मूल्यांकन करना।

**शोध समस्या:**

वर्तमान शिक्षा एवं प्रशिक्षण व्यवस्था किस सीमा तक समकालीन राजनीतिक चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम है तथा भारतीय ज्ञान प्रणाली इस दिशा में किस प्रकार एक प्रभावी वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकती है?

**साहित्य समीक्षा:**

ज्ञान-आधारित राष्ट्र निर्माण, शिक्षा, क्षमता निर्माण तथा राजनीतिक सुदृढ़ता के संदर्भ में विभिन्न भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने अपने-अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। इन विचारों का समन्वित अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि समकालीन राजनीतिक चुनौतियों के समाधान के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, साथ ही मूल्य-आधारित ज्ञान प्रणाली की प्रासंगिकता भी निरंतर बढ़ रही है।

भारतीय चिंतन परम्परा में शिक्षा को सदैव व्यक्ति और समाज के समग्र विकास का माध्यम माना गया है। दार्शनिक चिंतक सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारतीय दर्शन की व्याख्या करते हुए यह प्रतिपादित किया कि शिक्षा का उद्देश्य केवल बौद्धिक उन्नति नहीं, बल्कि नैतिक चेतना और आध्यात्मिक संतुलन का विकास भी है। उनके अनुसार राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में शिक्षा वह माध्यम है, जो नागरिकों को उत्तरदायी, विवेकशील और सामाजिक रूप से संवेदनशील बनाती है। इसी प्रकार श्री अरविन्द ने मानव विकास की समग्र अवधारणा प्रस्तुत करते हुए शिक्षा को चेतना के उत्कर्ष और सामाजिक परिवर्तन का साधन माना। उनके विचारों में यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि राष्ट्र की प्रगति तभी संभव है, जब व्यक्ति के भीतर निहित संभावनाओं का समुचित विकास किया जाए।

स्वामी विवेकानन्द ने भी शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का प्रमुख आधार माना और यह प्रतिपादित किया कि चरित्र निर्माण, आत्मविश्वास तथा नेतृत्व क्षमता का विकास शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। उनके अनुसार ऐसी शिक्षा, जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर और समाजोपयोगी बनाए, वही वास्तविक राष्ट्र निर्माण की दिशा में योगदान देती है। महात्मा गांधी ने "नई तालीम" की अवधारणा के माध्यम से शिक्षा को श्रम, नैतिकता और सामुदायिक जीवन से जोड़ने का प्रयास किया। गांधी जी के विचारों में शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक समानता, ग्राम स्वावलंबन और लोकतांत्रिक सहभागिता को सुदृढ़ करना था, जो आज के सहभागी शासन की अवधारणा से मेल खाता है।

आधुनिक भारतीय समाजशास्त्री एस. सी. दुबे ने भारतीय समाज की संरचना और परिवर्तनशीलता का विश्लेषण करते हुए यह बताया कि सामाजिक विकास और राजनीतिक स्थिरता के लिए शिक्षा एवं सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। इसी संदर्भ में कोठारी आयोग की रिपोर्ट ने शिक्षा को राष्ट्रीय विकास का प्रमुख साधन बताते हुए पाठ्यक्रम सुधार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा सामाजिक उत्तरदायित्व के विकास पर बल दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भी समकालीन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बहु विषयी शिक्षा, नैतिक मूल्यों और कौशल विकास के समन्वय की आवश्यकता को रेखांकित किया है।

पाश्चात्य विद्वानों के विचार भी इस विमर्श को व्यापक आयाम प्रदान करते हैं। गैब्रियल आलमंड और सिडनी वर्बा ने "नागरिक संस्कृति" की अवधारणा के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि लोकतंत्र की सफलता केवल संस्थागत संरचनाओं पर निर्भर

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

नहीं होती, बल्कि नागरिकों की सहभागिता, विश्वास और राजनीतिक संस्कृति पर भी आधारित होती है। उनके अनुसार शिक्षा नागरिकों को लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डेविड ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था के विश्लेषण में यह बताया कि किसी भी राजनीतिक प्रणाली की स्थिरता उसके इनपुट और आउटपुट के संतुलन पर निर्भर करती है, जिसमें नागरिकों की अपेक्षाएँ और शासन की प्रतिक्रियाएँ शामिल होती हैं।

माइकल एपल ने शिक्षा और शक्ति संबंधों का विश्लेषण करते हुए यह प्रतिपादित किया कि पाठ्यक्रम केवल ज्ञान का संप्रेषण नहीं करता, बल्कि वह सामाजिक संरचनाओं और राजनीतिक विचारधाराओं को भी प्रभावित करता है। पाउलो फ्रेइरे ने आलोचनात्मक शिक्षा की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए यह बताया कि शिक्षा को दमनकारी संरचनाओं से मुक्त कर नागरिकों को जागरूक और सशक्त बनाने का माध्यम बनाया जाना चाहिए। उनके विचार लोकतांत्रिक सहभागिता और सामाजिक न्याय के संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक हैं।

अमर्त्य सेन ने "विकास के रूप में स्वतंत्रता" की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिपादित किया कि वास्तविक विकास तभी संभव है, जब व्यक्तियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसरों तक समान पहुँच प्राप्त हो। उनके अनुसार क्षमता निर्माण राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का मूल तत्व है, क्योंकि यह नागरिकों को अपनी संभावनाओं को साकार करने में सक्षम बनाता है। मार्थानुसबाम ने भी मानव विकास के संदर्भ में शिक्षा को लोकतांत्रिक मूल्यों और वैश्विक नागरिकता के विकास का प्रमुख साधन माना।

जुर्गनहा बर्मास ने सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा के माध्यम से संवाद, विमर्श और सहमति निर्माण को लोकतंत्र का आधार बताया। उनके विचार यह संकेत करते हैं कि प्रभावी राजनीतिक व्यवस्था के लिए संवाद कौशल, सामाजिक संवेदनशीलता और सहभागी दृष्टिकोण का विकास अत्यंत आवश्यक है।

उपरोक्त साहित्य समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय और पाश्चात्य दोनों ही विद्वानों ने शिक्षा, क्षमता निर्माण और लोकतांत्रिक संस्कृति के बीच गहरे संबंध को स्वीकार किया है। तथापि, भारतीय ज्ञान प्रणाली के समग्र दृष्टिकोण; जिसमें नैतिकता, आध्यात्मिकता, सामाजिक समरसता और लोककल्याण का समन्वय है, को समकालीन राजनीतिक चुनौतियों के समाधान में व्यवस्थित रूप से लागू करने पर अभी और अधिक शोध की आवश्यकता है। यही इस अध्ययन की प्रासंगिकता और योगदान को रेखांकित करता है।

**शोध पद्धति:**

यह अध्ययन मुख्यतः वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक एवं व्याख्यात्मक पद्धति पर आधारित है। द्वितीयक स्रोतों जैसे पुस्तकों, शोध-पत्रों, शिक्षा नीति दस्तावेजों एवं सरकारी रिपोर्टों का उपयोग किया गया है।

**सैद्धांतिक रूपरेखा:**

इस अध्ययन की सैद्धांतिक रूपरेखा ज्ञान-आधारित राष्ट्र निर्माण की अवधारणा को केंद्र में रखते हुए भारतीय ज्ञान प्रणाली, शैक्षिक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम रूपांतरण तथा क्षमता निर्माण के मध्य अंतर्संबंधों को स्पष्ट करती है। यह रूपरेखा इस धारणा पर

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

दलीप सिंह बिष्ट (2026). भारतीय ज्ञान प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में शैक्षिक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम रूपांतरण एवं क्षमता निर्माण: समकालीन राजनीतिक चुनौतियाँ. International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews, 5(8),97-108.

आधारित है कि समकालीन राजनीतिक चुनौतियों का समाधान केवल नीतिगत या संस्थागत उपायों से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए ज्ञान, मूल्य एवं व्यवहारिक दक्षता के समन्वित विकास की आवश्यकता होती है।

भारतीय ज्ञान प्रणाली इस मॉडल का मूल वैचारिक आधार प्रस्तुत करती है, जिसमें नैतिकता, सहअस्तित्व, लोककल्याण, समग्र विकास तथा सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे तत्व निहित हैं। ये तत्व शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से व्यक्तियों एवं नागरिकों में विकसित किए जा सकते हैं, जिससे वे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में अधिक सक्रिय, जागरूक एवं उत्तरदायी भूमिका निभाने में सक्षम बन सकें।

**मॉडल की व्याख्या:**

इस सैद्धांतिक मॉडल के अनुसार भारतीय ज्ञान प्रणाली राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में एक आधारभूत प्रेरक तत्व के रूप में कार्य करती है। यह प्रणाली शिक्षा को केवल सूचना या कौशल अर्जन तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उसे नैतिकता, सामाजिक समरसता तथा लोकहित से जोड़ती है। जब शिक्षा व्यवस्था में भारतीय ज्ञान परम्परा के मूल्य समाहित किए जाते हैं, तब शैक्षिक प्रशिक्षण अधिक अर्थपूर्ण एवं व्यवहारिक बन जाता है।

परिणामस्वरूप पाठ्यक्रम रूपांतरण की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है, जिसमें नैतिक शिक्षा, नागरिक उत्तरदायित्व, सामुदायिक सेवा एवं नेतृत्व प्रशिक्षण जैसे घटकों को समाविष्ट किया जाता है। यह रूपांतरण विद्यार्थियों एवं नागरिकों में समग्र क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करता है। क्षमता निर्माण के अंतर्गत निर्णय क्षमता, संवाद कौशल, सामाजिक संवेदनशीलता तथा लोकतांत्रिक सहभागिता जैसे गुण विकसित होते हैं, जो प्रभावी राजनीतिक भागीदारी और उत्तरदायी नेतृत्व के लिए आवश्यक हैं।

जब नागरिक इन क्षमताओं से सुसज्जित होते हैं, तब राजनीतिक सशक्तिकरण और लोकतांत्रिक सुदृढ़ता की प्रक्रिया को बल मिलता है। सहभागी शासन, पारदर्शिता तथा जनविश्वास में वृद्धि होती है, जिससे राजनीतिक प्रणाली अधिक स्थिर एवं उत्तरदायी बनती है। अंततः यह समूची प्रक्रिया ज्ञान-आधारित राष्ट्र निर्माण को साकार करने में सहायक सिद्ध होती है, जहाँ विकास केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित न रहकर सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक समरसता एवं नैतिक नेतृत्व के साथ संतुलित रूप में आगे बढ़ता है।

**भारतीय ज्ञान प्रणाली और राष्ट्र निर्माण:**

भारतीय ज्ञान प्रणाली राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को केवल भौतिक या संस्थागत विकास तक सीमित न रखकर उसे मूल्य परक, समावेशी एवं समग्र दृष्टिकोण से देखने पर बल देती है। भारतीय ज्ञान परम्परा में "वसुधैव कुटुम्बकम्", "सर्वे भवन्तु सुखिनः" तथा "लोक संग्रह" जैसे सिद्धांत मानव समाज के व्यापक कल्याण, सह अस्तित्व और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को सुदृढ़ करते हैं। ये आदर्श न केवल सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता को प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि राजनीतिक जीवन में नैतिकता, पारदर्शिता और लोकहित की प्राथमिकता को भी सुनिश्चित करने की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इस प्रणाली के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल आजीविका अर्जन या तकनीकी दक्षता तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास का माध्यम भी है।

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

दलीप सिंह बिष्ट (2026). भारतीय ज्ञान प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में शैक्षिक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम रूपांतरण एवं क्षमता निर्माण: समकालीन राजनीतिक चुनौतियाँ. International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews, 5(8),97-108.

ज्ञान-आधारित राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में यह आवश्यक हो जाता है कि शिक्षा व्यवस्था आलोचनात्मक चिंतन, नैतिक नेतृत्व, नवाचार, सामाजिक संवेदनशीलता तथा सामुदायिक सहभागिता जैसे गुणों के विकास को प्राथमिकता दे। भारतीय ज्ञान प्रणाली इन आयामों को एकीकृत करते हुए व्यक्ति और समाज के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है, जिससे नागरिकों में उत्तरदायी व्यवहार, लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता और राष्ट्रीय हितों के प्रति सजगता विकसित हो सके। इस प्रकार, भारतीय ज्ञान परम्परा पर आधारित शिक्षा एवं प्रशिक्षण राष्ट्र निर्माण को अधिक सहभागी, न्यायसंगत और सतत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

**समकालीन राजनीतिक चुनौतियाँ:**

**1. लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण:**

समकालीन राजनीतिक परिदृश्य में लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण एक गंभीर चुनौती के रूप में उभर रहा है। लोकतंत्र केवल चुनावी प्रक्रिया तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सहिष्णुता, संवाद और नागरिक सहभागिता जैसे मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित होता है। वर्तमान समय में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की तीव्रता, सत्ता प्राप्ति की आकांक्षा तथा वैचारिक असहिष्णुता के कारण इन मूल्यों में गिरावट देखने को मिल रही है। कई बार जनमत निर्माण में तर्क संगत विमर्श की अपेक्षा भावनात्मक एवं विभाजनकारी मुद्दों को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे लोकतांत्रिक संस्कृति कमजोर होती है। परिणामस्वरूप नागरिकों का संस्थाओं पर विश्वास कम होता है और लोकतंत्र की गुणवत्ता प्रभावित होती है। ऐसे परिदृश्य में मूल्य-आधारित शिक्षा, नागरिक प्रशिक्षण तथा समावेशी राजनीतिक संवाद की आवश्यकता और अधिक बढ़ जाती है।

**2. नेतृत्व संकट और राजनीतिक नैतिकता का अभाव:**

आधुनिक राजनीति में नेतृत्व संकट केवल योग्य व्यक्तियों की कमी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नैतिक मूल्यों, दूरदृष्टि और जनकल्याणकारी दृष्टिकोण के अभाव से भी जुड़ा हुआ है। प्रभावी नेतृत्व के लिए निर्णय क्षमता, संवेदनशीलता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व जैसे गुण आवश्यक होते हैं, किन्तु समकालीन राजनीतिक परिस्थितियों में कई बार अल्पकालिक लाभ, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और दलगत हितों को प्राथमिकता दी जाती है। इससे नीतियों की निरंतरता प्रभावित होती है और जनविश्वास में कमी आती है। राजनीतिक नैतिकता का अभाव प्रशासनिक तंत्र की कार्य क्षमता को भी प्रभावित करता है तथा शासन व्यवस्था में असंतोष उत्पन्न करता है। इस चुनौती के समाधान हेतु नेतृत्व प्रशिक्षण, नैतिक शिक्षा और मूल्यपरक राजनीतिक संस्कृति के विकास की आवश्यकता है, जिससे जनहित केंद्रित एवं उत्तरदायी नेतृत्व का निर्माण हो सके।

**3. सामाजिक एवं सांस्कृतिक ध्रुवीकरण:**

वैश्वीकरण, पहचान की राजनीति तथा सूचना प्रौद्योगिकी के तीव्र प्रसार के कारण समाज में विविध प्रकार के सामाजिक एवं सांस्कृतिक ध्रुवीकरण देखने को मिल रहे हैं। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र तथा विचारधारात्मक मतभेदों के आधार पर समाज के विभिन्न वर्गों के बीच दूरी बढ़ने लगी है, जिससे सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता प्रभावित होती है। कई बार राजनीतिक लाभ के लिए इन विभाजनों को और अधिक गहरा किया जाता है, जिससे सामूहिक हितों की अपेक्षा समूहगत हितों को प्राथमिकता मिलने लगती है। परिणामस्वरूप लोकतांत्रिक निर्णय-प्रक्रिया में संतुलन एवं समावेशिता का अभाव हो जाता है। इस स्थिति से निपटने के

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

दलीप सिंह बिष्ट (2026). भारतीय ज्ञान प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में शैक्षिक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम रूपांतरण एवं क्षमता निर्माण: समकालीन राजनीतिक चुनौतियाँ. International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews, 5(8),97-108.

लिए समावेशी शिक्षा, सांस्कृतिक संवाद और सहअस्तित्व की भावना को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है, ताकि समाज में विश्वास, सहयोग और साझी पहचान का विकास हो सके।

**4. नीतिगत असंतुलन एवं जन सहभागिता की कमी:**

समकालीन शासन व्यवस्था में नीतिगत असंतुलन और जन सहभागिता की कमी भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक चुनौती है। कई बार नीतियाँ पर्याप्त परामर्श, स्थानीय आवश्यकताओं के विश्लेषण तथा दीर्घकालिक प्रभावों के मूल्यांकन के बिना बनाई जाती हैं, जिससे उनके क्रियान्वयन में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। इसकेअतिरिक्त, नीति निर्माण एवं कार्यान्वयन की प्रक्रिया में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सीमित रहने के कारण जन अपेक्षाओं और नीतिगत परिणामों के बीच अंतर बढ़ जाता है। इससे शासन के प्रति असंतोष और अविश्वास की भावना विकसित हो सकती है। प्रभावी एवं संतुलित नीतियों के निर्माण हेतु आवश्यक है कि सहभागी शासन को प्रोत्साहित किया जाए तथा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के माध्यम से नागरिकों में जागरूकता, उत्तरदायित्व और सहभागिता की भावना विकसित की जाए। इन चुनौतियों का समाधान केवल संस्थागत सुधारों से नहीं, बल्कि मानवीय क्षमता निर्माण और मूल्य आधारित प्रशिक्षण से संभव है।

**शैक्षिक प्रशिक्षण एवं पाठ्यक्रम रूपांतरण:**

पाठ्यक्रम रूपांतरण का उद्देश्य शिक्षा को अधिक प्रासंगिक, समावेशी एवं व्यवहारिक बनाना है। भारतीय ज्ञान प्रणाली आधारित पाठ्यक्रम में कुछ प्रमुख बिन्दुओं पर ध्यान देना आवश्यक है:

**नैतिक शिक्षा:**

नैतिक शिक्षा शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आयाम है, जो व्यक्ति के चरित्र निर्माण, मूल्यबोध और सामाजिक उत्तरदायित्व को विकसित करने में सहायक होती है। समकालीन समय में जब राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, उपभोक्तावाद और व्यक्तिगत स्वार्थ की प्रवृत्तियाँ बढ़ रही हैं, तब नैतिक शिक्षा का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों में सत्यनिष्ठा, सहिष्णुता, करुणा, न्यायप्रियता और लोककल्याण की भावना का विकास किया जा सकता है। नैतिक शिक्षा केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित न होकर व्यवहारिक गतिविधियों, संवाद, केस-स्टडी तथा सामाजिक अनुभवों के माध्यम से प्रदान की जानी चाहिए। इससे नागरिकों में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता बढ़ेगी और एक उत्तरदायी राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में सहायता मिलेगी।

**नागरिक उत्तरदायित्व:**

नागरिक उत्तरदायित्व लोकतांत्रिक समाज की आधारशिला है, क्योंकि किसी भी शासन व्यवस्था की सफलता नागरिकों की सक्रिय भागीदारी और जागरूकता पर निर्भर करती है। शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नागरिक कर्तव्यों, संवैधानिक मूल्यों, मतदान, जननीति में सहभागिता तथा सामाजिक न्याय जैसे विषयों को समाहित करने से नागरिकों में उत्तरदायित्व की भावना विकसित की जा सकती है। जब व्यक्ति अपने अधिकारों के साथ-साथ अपने कर्तव्यों को भी समझने लगता है, तब वह समाज और

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

राष्ट्र के विकास में अधिक सकारात्मक भूमिका निभाता है। नागरिक उत्तरदायित्व का विकास शासन के प्रतिविश्वास को सुदृढ़ करता है तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है।

**सामुदायिक सेवा:**

सामुदायिक सेवा शिक्षा का एक व्यवहारिक पक्ष है, जो विद्यार्थियों को समाज की वास्तविक समस्याओं से जोड़ने का अवसर प्रदान करता है। इसके माध्यम से सहयोग, सहानुभूति, सामाजिक संवेदनशीलता और सामूहिक उत्तरदायित्व जैसे गुणों का विकास होता है। जब विद्यार्थी या युवा विभिन्न सामाजिक कार्यों; जैसे स्वच्छता अभियान, साक्षरता कार्यक्रम, पर्यावरण संरक्षण या ग्रामीण विकास में भाग लेते हैं, तब वे लोकतांत्रिक सहभागिता के महत्व को अनुभवात्मक रूप से समझते हैं। सामुदायिक सेवा समाज और शिक्षा के बीच सेतु का कार्य करती है तथा नागरिकों को सक्रिय, जागरूक और सहभागी बनने के लिए प्रेरित करती है।

**नेतृत्व प्रशिक्षण:**

नेतृत्व प्रशिक्षण समकालीन राजनीतिक एवं सामाजिक परिवेश में अत्यंत आवश्यक घटक बन चुका है। प्रभावी नेतृत्व केवल प्रशासनिक दक्षता तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें दूरदृष्टि, नैतिकता, संवाद कौशल, निर्णय क्षमता और संकट प्रबंधन जैसी विशेषताओं का समावेश होता है। शिक्षा प्रणाली में नेतृत्व प्रशिक्षण को शामिल करने से विद्यार्थियों और युवाओं में आत्मविश्वास, टीम-वर्क और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है। इसके अतिरिक्त, नेतृत्व प्रशिक्षण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सार्थक भागीदारी और नीति-निर्माण की समझ को भी सुदृढ़ करता है। इस प्रकार यह राष्ट्र निर्माण की दिशा में सक्षम, उत्तरदायी और संवेदनशील नेतृत्व तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

**क्षमता निर्माण और राजनीतिक सशक्तिकरण:**

क्षमता निर्माण केवल कौशल विकास नहीं, बल्कि निर्णय क्षमता किसी भी व्यक्ति, विशेष कर नेतृत्वकर्ता एवं जागरूक नागरिक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है। समकालीन राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिदृश्य में अनेक जटिल परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, जिनमें त्वरित, तर्कसंगत एवं दूरदर्शी निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। शिक्षा एवं प्रशिक्षण के माध्यम से विश्लेषणात्मक चिंतन, समस्या समाधान, विकल्पों का मूल्यांकन तथा परिणामों की पूर्वानुमान क्षमता विकसित की जा सकती है। निर्णय क्षमता का विकास न केवल प्रशासनिक दक्षता को सुदृढ़ करता है, बल्कि नीति-निर्माण की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी एवं उत्तरदायी भी बनाता है। इसके माध्यम से व्यक्ति व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर व्यापक सामाजिक एवं राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने में सक्षम बनता है।

**संवाद कौशल:**

संवाद कौशल लोकतांत्रिक समाज में सहमति निर्माण, मतभेदों के समाधान तथा प्रभावी नेतृत्व के लिए अनिवार्य तत्व है। समकालीन राजनीतिक वातावरण में विचारों की विविधता और सामाजिक जटिलताओं के कारण संवाद की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अभिव्यक्ति की स्पष्टता, सक्रिय श्रवण, तर्कपूर्ण प्रस्तुतीकरण

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

तथा सहानुभूतिपूर्ण संप्रेषण जैसे गुणों का विकास किया जा सकता है। प्रभावी संवाद न केवल राजनीतिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाता है, बल्कि नागरिकों और शासन के बीच विश्वास एवं सहयोग को भी सुदृढ़ करता है।

**सामाजिक संवेदनशीलता:**

सामाजिक संवेदनशीलता व्यक्ति को समाज के विभिन्न वर्गों की समस्याओं, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को समझने की क्षमता प्रदान करती है। यह गुण समावेशी विकास एवं न्यायपूर्ण शासन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब शिक्षा प्रणाली में विविधता, समानता, सहअस्तित्व और मानवाधिकार जैसे विषयों को समाहित किया जाता है, तब विद्यार्थियों में सामाजिक उत्तरदायित्व और सहानुभूति की भावना विकसित होती है। सामाजिक संवेदनशीलता नेतृत्व को अधिक मानवीय और जनकेन्द्रित बनाती है, जिससे नीतियाँ समाज के सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाई जा सकती हैं।

**लोकतांत्रिक सहभागिता:**

लोकतांत्रिक सहभागिता किसी भी लोकतंत्र की जीवंतता और स्थिरता का आधार होती है। नागरिकों की सक्रिय भागीदारी जैसे; मतदान, जनविमर्श, सामुदायिक निर्णय-प्रक्रिया और नीति-निर्माण में सहयोग लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाती है। शिक्षा एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों में जागरूकता, आत्मविश्वास और सहभागिता की भावना विकसित की जा सकती है। इससे शासन और समाज के बीच संवाद बढ़ता है तथा निर्णय-प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनती है। लोकतांत्रिक सहभागिता का विस्तार राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को अधिक समावेशी, संतुलित और सतत बनाने में सहायक सिद्ध होता है। भारतीय ज्ञान प्रणाली इन आयामों को समग्र रूप से विकसित करने का आधार प्रदान करती है।

**निष्कर्ष:**

अध्ययन के विश्लेषण से यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित होता है कि ज्ञान-आधारित राष्ट्र निर्माण की समकालीन अवधारणा को सुदृढ़ बनाने में भारतीय ज्ञान प्रणाली एक महत्वपूर्ण वैचारिक तथा व्यवहारिक आधार प्रदान करती है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में जहाँ लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण, नेतृत्व संकट, सामाजिक ध्रुवीकरण तथा नीतिगत असंतुलन जैसी चुनौतियाँ उभर रही हैं, वहाँ केवल संस्थागत सुधार पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि शिक्षा एवं प्रशिक्षण की प्रक्रियाओं में मूल्यों, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व के समन्वित समावेश की आवश्यकता है। भारतीय ज्ञान परम्परा में निहित समग्रता, सहअस्तित्व, लोककल्याण और सहभागिता के सिद्धांत नागरिकों एवं नेतृत्व दोनों के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक हो सकते हैं।

इस संदर्भ में मूल्य-आधारित पाठ्यक्रम रूपांतरण, व्यवहारिक प्रशिक्षण, सामुदायिक सहभागिता तथा समग्र क्षमता निर्माण मॉडल को अपनाना अत्यंत आवश्यक प्रतीत होता है, जिससे व्यक्तियों में निर्णय क्षमता, संवाद कौशल, सामाजिक संवेदनशीलता और लोकतांत्रिक सहभागिता जैसे गुणों का विकास संभव हो सके। इसके परिणामस्वरूप शिक्षा व्यवस्था केवल ज्ञानार्जन तक सीमित न रहकर उत्तरदायी नागरिकता, नैतिक नेतृत्व और सहभागी शासन की दिशा में भी सार्थक योगदान दे सकती है। अतः यह कहा जा सकता है कि भारतीय ज्ञान प्रणाली आधारित दृष्टिकोण न केवल लोकतांत्रिक सुदृढ़ता को बढ़ावा देता है, बल्कि एक समावेशी, संतुलित एवं सतत राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता रखता है, जो दीर्घकालीन राष्ट्र निर्माण के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है।

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

दलीप सिंह बिष्ट (2026). भारतीय ज्ञान प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में शैक्षिक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम रूपांतरण एवं क्षमता निर्माण: समकालीन राजनीतिक चुनौतियाँ. International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews, 5(8),97-108.

**नीतिगत सुझाव:**

**1. मूल्य-आधारित पाठ्यक्रम रूपांतरण को प्रोत्साहन:**

शिक्षा नीति निर्माताओं को चाहिए कि वे पाठ्यक्रम संरचना में नैतिकता, नागरिक उत्तरदायित्व, सहअस्तित्व तथा लोककल्याण जैसे भारतीय ज्ञान परम्परा आधारित मूल्यों को समाहित करें। इससे शिक्षा केवल ज्ञानार्जन का माध्यम न रहकर व्यक्तित्व निर्माण और उत्तरदायी नागरिकता के विकास का साधन बन सकेगी।

**2. नेतृत्व एवं राजनीतिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संस्थागत विकास:**

विश्वविद्यालयों और प्रशिक्षण संस्थानों में युवाओं तथा जनप्रतिनिधियों के लिए नेतृत्व विकास, लोकतांत्रिक संवाद, नीति-निर्माण और संकट प्रबंधन से संबंधित विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाने चाहिए। इससे दूरदर्शी, नैतिक एवं उत्तरदायी नेतृत्व के निर्माण में सहायता मिलेगी।

**3. सहभागी शासन को सुदृढ़ करना:**

नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में नागरिकों, स्थानीय समुदायों और नागरिक समाज संगठनों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। जन सुनवाई, सामाजिक अंकेक्षण/आडिट और परामर्श तंत्र जैसे उपाय शासन को अधिक पारदर्शी एवं उत्तरदायी बना सकते हैं।

**4. सामुदायिक सेवा एवं अनुभवात्मक अधिगम को अनिवार्य बनाना:**

शैक्षिक संस्थानों में सामुदायिक सेवा, इंटर्नशिप, ग्रामीण भ्रमण एवं सामाजिक परियोजनाओं को पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए। इससे विद्यार्थियों में सामाजिक संवेदनशीलता, सहयोग और लोकतांत्रिक सहभागिता की भावना विकसित होगी।

**5. क्षमता निर्माण के समग्र मॉडल का विकास:**

सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा ऐसे क्षमता निर्माण मॉडल विकसित किए जाने चाहिए, जिनमें निर्णय क्षमता, संवाद कौशल, नैतिक नेतृत्व और सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे आयामों का समावेश हो। इससे प्रशासनिक दक्षता और जनविश्वास दोनों को सुदृढ़ किया जा सकेगा।

**6. डिजिटल एवं नागरिक साक्षरता कार्यक्रमों का विस्तार:**

समकालीन राजनीतिक एवं सामाजिक चुनौतियों को देखते हुए डिजिटल साक्षरता, तथ्य परक सोच और जिम्मेदार सूचना उपयोग से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इससे नागरिकों में जागरूकता बढ़ेगी और लोकतांत्रिक विमर्श अधिक संतुलित एवं रचनात्मक बन सकेगा।

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

**7. भारतीय ज्ञान प्रणाली पर आधारित शोध एवं नवाचार को प्रोत्साहन:**

उच्च शिक्षा संस्थानों में भारतीय ज्ञान परम्परा के समकालीन अनुप्रयोगों पर शोध परियोजनाएँ, संगोष्ठियाँ एवं बहुविषयी अध्ययन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे नीति निर्माण, शिक्षा सुधार एवं सामाजिक विकास के लिए नए वैचारिक एवं व्यवहारिक मॉडल विकसित किए जा सकेंगे।

### AUTHOR(S) CONTRIBUTION

The writers affirm that they have no connections to, or engagement with, any group or body that provides financial or non-financial assistance for the topics or resources covered in this manuscript.

### CONFLICTS OF INTEREST

The authors declared no potential conflicts of interest with respect to the research, authorship, and/or publication of this article.

### PLAGIARISM POLICY

All authors declare that any kind of violation of plagiarism, copyright and ethical matters will take care by all authors. Journal and editors are not liable for aforesaid matters.

### SOURCES OF FUNDING

The authors received no financial aid to support for the research.

## संदर्भ सूची:

1. मिश्र, नित्यानंद एवं पाण्डे, शिवचरण; 1998: पर्यावरण संस्कृति प्रदूषण एवं संरक्षण, अल्मोड़ा बुक डिपो,अल्मोड़ा।
2. विकास, व्यास, 2012: भारतीय धर्मशास्त्र को विश्वेश्वर समृति का योगदान, नवभारत प्रकाशन जोधपुर।
3. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020)।
4. तिलक, रघुकुल; 1972: लोकतंत्र स्वरूप और समस्यायें, उत्तर प्रदेश, हिन्दी ग्रंथ अकादमी, लखनऊ
5. सरोज, गुप्ता, 2023: भारतीय ज्ञान परम्परा: विविध आयाम, यजूर पब्लिकेशन हाउस बोरवल।
6. कपिलदेव, द्विवेदी, 2022: वेदों में विज्ञान, विश्वभारती अनुसंधान परिषद,भदोही।
7. राजपूत ,जगमोहनसिंह; 2024: भारतीय विरासत और वैश्विक समस्यायें, किताबघर प्रकाशन दिल्ली।
8. नौटियाल, शिवानंद; 1994: भारत के वन्यजीव विहार, सामयिक प्रकाशन, दिल्ली
9. मणि, दिनेश, 2015: ग्लोबल वार्मिंग, सत्यसाहित्य प्रकाशन दिल्ली।

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

दलीप सिंह बिष्ट (2026). भारतीय ज्ञान प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में शैक्षिक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम रूपांतरण एवं क्षमता निर्माण: समकालीन राजनीतिक चुनौतियाँ. International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews, 5(8),97-108.

10. त्रिवेदी, गिराजाशंकर तथा अग्रवाल, अमिता;1989: महाभारत के वन और वृक्ष, चाँदना प्रिंटिंग वर्कस, देहरादून

11. राधाकृष्णन, सर्वपल्ली (2009: भारतीय दर्शन, राजपाल एंड संस, नईदिल्ली।

12. अरविन्द, श्री (2011):. मानव एकता का आदर्श, श्रीअरविन्द आश्रम प्रकाशन, पुदुचेरी।

13. विवेकानन्द, स्वामी (2013): शिक्षा और राष्ट्रनिर्माण, अद्वैत आश्रम, कोलकाता।

14. गांधी, मोहनदास करमचन्द (2009): हिन्द स्वराज, नवजीवन प्रकाशन, अहमदाबाद।

15. तिलक, बालगंगाधर (2010): गीता रहस्य, लोकमान्य तिलक मंडल, पुणे।

16. दुबे, एस. सी. (2005): भारतीय समाज, नेशनल बुक ट्रस्ट, नईदिल्ली।

17. कोठारी, डी. एस. (1966): शिक्षा और राष्ट्रीय विकास (कोठारी आयोग रिपोर्ट), भारत सरकार, नई दिल्ली।

18. भारत सरकार (2020): राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिक्षा मंत्रालय, नईदिल्ली।

19. अलमंड, गैब्रियल एवं वर्बा, सिडनी (2008). नागरिक संस्कृति, सेज पब्लिकेशन।

20. ईस्टन, डेविड (1990): राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण, प्रेंटिस हॉल।

21. एपल, माइकलडब्ल्यू. (2004): शिक्षा और शक्ति, रूटलेज प्रकाशन।

22. फ्रेइरे, पाउलो (2014): उत्पीड़ितों की शिक्षा, ब्लूम्सबरी अकादमिक।

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License